>

Title: Need to include Bargi Dam Canal Irrigation Project of Madhya Pradesh under National Project.

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति जी, मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे देश के संविदान में लिखा है कि भारत सरकार के आर्थिक संसाधनों में प्रत्येक नागरिक एवम् सभी भूभाग को बराबर का अधिकार है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से यह देखने में मिल रहा है कि केन्द्र सरकार आर्थिक संसाधनों को पहचान-पहचान कर सिर्फ वोटों को ध्यान में रखकर बंटवारा कर रही है। यही कारण है कि गैर कांग्रेस शासित राज्य सरकारें द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है कि उनके साथ केन्द्र सरकार द्वारा लगातार भेदभाव किया जा रहा है।

मैं उदाहरण के रूप में मध्य प्रदेश की एक बड़ी सिंचाई योजना का जिक्र करना चाहता हूं। भारत सरकार ने देश की कुछ बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर उन्हें आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया है। उसीके तहत मध्य प्रदेश सरकार ने बरगी बांध की दाई तट नहर, जिसमें चार जिलों की लगभग एक करोड़ आबादी लाभान्वित होने वाली है, उस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने हेतु सभी नियमों का पालन करते हुए राज्य शासन ने भेजा है। उसमें लगभग 3400 करोड़ रुपए का व्यय होना है। विगत तीन वर्षों से मध्य प्रदेश के सतना, रीवा, कटनी और जबलपुर जिलों के लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं लगातार इस मुद्दे को सदन में तथा माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय जल संसाधन मंत्री जी के समक्ष उठाता रहा हूं और उन्हें विषय से अवगत करा चुका हूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर उस क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय करने का कष्ट करे।